

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारी:-कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या- 64/2020
GCMS CASE NO-2020/00064

दायरा दिनांक 19.10.2020

देवेन्द्र कुमार पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ़
—प्रार्थी

बनाम

- 1.रामस्वरूप पुत्र लाधूराम जाति बिश्नोई साकिन चक 6 एलकेएस लख्खासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजरव सूरतगढ़
3. उप-पंजीयक सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970
सहपठित नियम 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित:-

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज

—: निर्णय :-

दिनांक : 19 .11.2024

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने सही तथ्य छिपाकर व झूठे तथ्य पेशकर उपनिवेशन तहसीलदार से रोही सरदारपुरा लाडाना के खसरा न. 98 में 25.00 बीघा रकबा सर्वप्रथम टीसी आवंटन करवाया व तत्पश्चात दिनांक 15.05.1992 को उक्त रकबा टीसी से पुख्ता करवाया तथा तदुपरांत तहसीलदार सूरतगढ़ से दिनांक 13.08.2008 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। अप्रार्थी के उक्त टीसी आवंटन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी का अगूठा लगा हुआ है, जबकि सन 1984-85 में अप्रार्थी 1 कक्षा 8 वीं पास था तथा गांव लख्खासर तहसील पीलीबंगा का रहने वाला ही नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 गांव लख्खासर तहसील पीलीबंगा का रहने वाला है। वह कभी भी गांव सरदारपुरा लाडाना में रहा ही नहीं। उसने तो झूठा पता दिखाकर खुद को गांव सरदारपुरा लाडाना का वाशिन्दा दिखाकर रोही सरदारपुरा लाडाना में आवंटन करवाया है। प्रथमतः अप्रार्थी संख्या 1 को कभी टीसी आवंटन हुआ ही नहीं। अप्रार्थी को किया गया उक्त टीसी आवंटन नियम विरुद्ध है क्योंकि तहसीलदार को बिना कमेटी की राय लिये आवंटन करने का अधिकार नहीं है। जैर प्रार्थना पत्र रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी कब्जा काशत नहीं रहा तथा ना ही कभी अप्रार्थी के नाम से रकम राज व मालकाना जमा करवाया गया। उक्त टीसी का कभी नवीनीकरण भी नहीं हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सही तथ्य छिपाकर व झूठे तथ्य पेश करके आवंटन नियम 1975 के नियमों में आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ से दिनांक 15.05.1992 को रकबा पुख्ता आवंटन करवा लिया। जबकि अप्रार्थी का टीसी नवीनीकरण कभी हुआ ही नहीं। जैर प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा। अप्रार्थी संख्या 1 को तो यह भी जानकारी नहीं है कि उसका रकबा कहां स्थित है तथा इस रकबा के आसा-पासा उत्तर दक्षिण में किसका रकबा है। इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी के पास चक 6 एसकेएस के पत्थर न. 6/273 (16) के किला न. 6 ता 25 व पत्थर न. 6/275 के किला न. 1 ता 3 इस प्रकार इन दोनो पत्थर न. में 5.870 है 0 कमाण्ड रकबा सन 1984-85 से पूर्व का खातेदारी रकबा है व तहसील पीलीबंगा के चक 21 एमओडी के पत्थर न.6/267 के किला न. 6, 6 ता 7, 10 ता 25 में 4.680 है 0 में 1/2 हिस्सा अनकमाण्ड गय खाला रास्ता व तहसील कोलायत नई तहसील बज्जू के रोही बीठनोक के खसरा न. 428 में 25.00 बीघा रकबा बैयनामा दिनांक 17.10.1969 से खरीदकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होकर उसके कब्जा काशत में चला आ रहा है। जब अप्रार्थी के पासस पहले से इतना बड़ा नहरी व बारानी रकबा है तो अप्रार्थी का अन्य रकबा टीसी आवंटन या खातेदारी अधिकार निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)



प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई एवं अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया किया शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य एवं शिकायत को साबित करने वाले दस्तावेजात एवं तथ्य ही मेरी बहस है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को टी.सी. भूमि को आवंटन करवाने का पात्र मानते हुए ही रोही सरदारपुरा लाडाना के खसरा नम्बर 98 में 25 बीघा बारानी भूमि वर्ष 1985 संवत् 2041 में टी.सी. पर आवंटन की जाकर कब्जा काश्त अप्रार्थी को सौंप दिया गया था। तब से लेकर आज तक कब्जा काश्त पिछले लगभग 39 वर्षों से अप्रार्थी व उसके परिवार के पास चला आ रहा है। जैरप्रकरण रकबा दिनांक 15.05.1992 को पुख्ता आवंटन कर दिया गया। पूरी जांच करने के बाद ही पुख्ता आवंटन किया गया था। तमाम शर्तों की पूर्ति होने पर आज से 17 वर्ष पूर्व दिनांक 13.08.2008 को सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार जारी कर दिये गये थे। शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य झूठे हैं। मुझ अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। शिकायतकर्ता स्वयं मान रहे हैं कि वर्ष 1985 संवत् 2040-41 में रकबा टी.सी. आवंटन हुआ। टी.सी. पट्टा का नवीनीकरण होता रहा व बाद में वर्ष 1992 में पूरी जांच करके आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा पुख्ता आवंटन किया गया। समस्त शर्तों की पूर्ति करने के बाद वर्ष 2008 में खातेदारी भी जारी की गई। आज राजस्व रिकार्ड में पिछले 17 वर्षों से बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। शिकायतकर्ता का कथन है कि अप्रार्थी ग्राम सरदारपुरा लाडाना का रहने वाला नहीं हैं व तहसील पीलीबंगा के लखासर गांव का भी रहने वाला नहीं हैं तो फिर अप्रार्थी कहां का रहने वाला हैं। टी.सी. आवंटन में मजमें आम में पटवारी हल्का व गिरदावर ने जांच करके अप्रार्थी को गांव सरदारपुरा लाडाना का वांशिदा बताया है व वहीं का वांशिदा मान कर ही भूमि टी.सी. आवंटन की गई थी व कब्जा काश्त रकम मालकाना जमा करवाने के बाद ही टी.सी. आवंटन का नवीनीकरण होता रहा है। शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य झूठे हैं। रकबा आवंटन हुए 40 वर्ष हो गये हैं। आवंटन के समय तहसील में भीड़ बहुत रहती थी व अरायजनवीस दरखास्त लिखवाने वाले को कहता था कि अंगुठा लगा तो काश्तकार तुरन्त दरखास्त पर अंगुठा लगा देता था। शिकायतकर्ता का यह कहना कि प्रथम तो अप्रार्थी को रकबा टी.सी. आवंटन हुआ ही नहीं, जब टी.सी. आवंटन हुआ तो आज किस आदेश के विरुद्ध शिकायत की गई है। तहसीलदार द्वारा टी.सी. आवंटन कानूनसम्मत सब नियमों की पालना करते हुए ही टी.सी. आवंटन किया गया था। अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये हैं। शिकायतकर्ता ने मुझ अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए झूठे तथ्य दर्ज करवाये हैं। प्रार्थना पत्र में चक 6 एस.के.एस. व 21 एम.ओ.डी. का रकबा बताया है उस बाबत शिकायतकर्ता द्वारा झूठे तथ्य प्रस्तुत किये हैं, तहसील पीलीबंगा का जो रकबा बताया है वह रकबा अप्रार्थी के नाम से अपने पिता से विरासतन आया हुआ है, उसमें अप्रार्थी के अगर कोई रकबा खरीद का है तो वह पिता ने अपनी खातेदारी पैतृक भूमि की आय से ही खरीदा हुआ है तो उसमें अप्रार्थी के पुत्रों का जन्म से हक व हिस्सा बनता है जिसमें अप्रार्थी का 1/5 वां हक व हिस्सा ही बनता है। इस प्रकार अप्रार्थी ने न तो कोई रकबा छिपाया है व न ही शिकायत वाला रकबा गलत तरीके से आवंटन करवाया है। अप्रार्थी को रकबा नियमानुसार ही आवंटन किया गया है। शिकायत झूठी व निराधार की हुई होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य छिपाया ही नहीं व न ही धारा 11/14 को. एक्ट के तहत तथ्य छिपाने बाबत इस अदालत में सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है, चूंकि रकबा कोलोनी एरिया का नहीं होने से यह धारा लागू ही नहीं होती। अतः शिकायत का प्रार्थना पत्र शुरु से ही सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से शिकायत निरस्त होने योग्य है। अगर टी.सी. आवंटन कानूनसम्मत नहीं हो तो टी.सी. आवंटन के समय तक ही उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो सकती है। मौजूदा प्रकरण में तो रकबा सन् 1992 में ही पुख्ता आवंटन हो जाने से उस पर आवंटन नियम 1975 लागू हो गये थे व उसके बाद सन् 2008 में रकबा उपनिवेशन विभाग से बाहर हो जाने पर रकबा राजस्थान भू-राजस्व(कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के तहत 2008 में ही खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये थे। खातेदारी अधिकार जारी करने से पूर्व पुनः सभी पहलुओं की जांच करने के उपरान्त ही खातेदारी अधिकार जारी किये गये थे। जैर शिकायत रकबा वर्ष 2008 से ही खातेदारी होकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज होकर लगातार कब्जा काश्त में चला आ रहा है। किसी व्यक्ति ने टी.सी. आवंटन गलत करवा लिया है तो टी.सी. आवंटन रहने के दौरान ही शिकायत की जा सकती है, रकबे का टाईटल बदलने के बाद टी.सी. आवंटन की कमी का सहारा लेकर आगे का पुख्ता आवंटन या खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस की पक्ष में न्यायिक

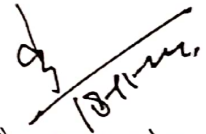
दृष्टांत AIR 1994 P 1128, RRT 2019(1) P 539, RBJ2001 P 126, SSC 1994 P 575, RBJ 1995 HC P 780, RRD 1999 P 128, RRT 2016(1) P 82, RRT 2019(2) P 1065, RRT 2019(1) P 539, RBJ 2016 P 474, RRT 2010(1) P 157, RRD 2001(2) P 206, RRD 1982 P 339, की ओर ध्यान दिलाया।

अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकर राज ने दौराने बहस राज्य पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने पिता की भूमि को छिपाकर जैर प्रार्थना पत्र रकबा तथ्य छिपाकर आवंटन करवाया है। जैर प्रार्थना पत्र रकबा खसरो का बारांनी रकबा है। अप्रार्थी के पिता से आये नोशनल हिस्सा मिलाने पर भी रकबा 25 बीघा कमाण्ड अथवा 50 बीघा अनकमाण्ड से अधिक भूमि नहीं बनती है। टीसी से पुख्ता आवंटन की कार्यवाही के दौरान भी आवंटन अधिकारी के समक्ष तथ्य छुपाकर आवंटन करवाने संबंधी कोई तथ्य सामने नहीं आये तथा नहीं आवंटन अधिकारी के समक्ष ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई। पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के कोई तथ्य आवंटन एवं आवंटन के पश्चात छुपाया जाना साबित नहीं होता वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने के कारण खारिज करना हम उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त न्यायाधीश
सूरतगढ़ (सूरतसंघनगर)